शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 1–8 अगस्त 2022 मूल्य पांच रूपए

प्रबोध सक्सेना की जमानत रद्द करवाने पर सीबीआई में शुरू हुआ पुनर्विचार

- राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में सील्ड कवर प्रक्रिया न अपनाना बना बड़ा कारण
- शिमला और दिल्ली में दोनों जगह सरकारी आवास होना भी है प्रभाव का परिणाम

शिमला/शैल। जयराम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के साथ आई एम एक्स मीडिया मामले में सह अभियुक्त हैं। यह मामला सीबीआई ने मई 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा अन्य अपराधिक धाराओं में दर्ज किया था। यह मामला दर्ज होने के बाद फरवरी 2020 में सक्सेना को इस में जमानत लेनी पड़ी है। इस मामले के चलते सक्सेना का नाम संदिग्ध आचरण श्रेणी के अधिकारियों की सूची में आ जाता है। इसी के साथ मामले के निपटारे तक सक्सेना को महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार नहीं दिया जा सकता। पदोन्नति में भी उनका नाम सील्ड कवर में रखा जायेगा। ऐसा सरकार के नियमों में कहा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह व्यवस्था अपने फैसलों में दी हुई है।

लेकिन जयराम सरकार ने सरकारी नियमों और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए सक्सेना को न केवल महत्वपूर्ण विभागों से नवाजा है बल्कि इस मामले के चलते उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव भी पदोन्नत कर दिया है। यही नहीं सक्सेना को शिमला के साथ दिल्ली में भी समानान्तर तैनाती देकर वहां भी सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। इससे सक्सेना के राज्य सरकार के साथ ही केंद्र में भी प्रभाव का पता चलता है। क्योंकि दिल्ली में आवास की सुविधा केन्द्र के ऐस्टेट निदेशालय द्वारा दी गयी है। राज्य सरकार ने जहां सक्सेना के मामले में सारे नियमों कानूनों को अंगूठा दिखाया है वहीं पर गैर कर्मचारियों के मामलों में इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सचिवालय में घटे सैनिटाइजर घोटाले में आरोपित एक कर्मचारी का मामला पदोन्नति के लिये विचार में ही नहीं लिया गया। जबकि कर्मचारी उसका मामला नियमों के अनुसार सील्ड कवर में रखने का आग्रह करता रहा। शायद इस डी पी सी के सक्सेना स्वयं एक सदस्य थे। अब जब सक्सेना का मामला सार्वजनिक रूप से चर्चा में आ गया है तबसे पूरे कर्मचारी वर्ग में यह चर्चा का विषय बन गया है। सरकार पर आरोप लग रहा है कि बड़े और प्रभावशाली अधिकारियों के लिए सरकार के नियम कानून और हैं तथा छोटे कर्मचारियों के लिये अलग हैं। जय राम सक्सेना पर जिस कदर मेहरबान हैं इससे उनके प्रभावशाली होने का सीधा प्रमाण मिल जाता है। स्वभाविक है कि जो अधिकारी शिमला में सरकारी आवास लेने के साथ ही दिल्ली में केन्द्र से भी आवास की सुविधा हासिल कर सकता है तो वह निश्चित रूप से अपने मामले के प्रबंधन का भी हर संभव प्रयास करेगा ही। क्योंकि प्रदेश सरकार पूरा सहयोग दे रही है। आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में सिविल सर्विसेज बोर्ड विचार करता है। सक्सेना की पदोन्नति से स्पष्ट हो जाता है कि बोर्ड ने सीबीआई में मामला दर्ज होने का संज्ञान नहीं लिया है। बोर्ड ने यह नजरअंदाजगी किसके दबाव या प्रभाव में की है यह एक अलग चर्चा का विषय बन गया है। अब जब से यह मामला समाचारों का विषय बना है तब से यह फिर सीबीआई में चर्चा का विषय बन गया है। यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि जिस अधिकारी के लिये राज्य सरकार सारे स्थापित नियमों कानूनों को अंगूठा दिखा सकती है वह अपने मामले से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास क्यों नहीं करेगा। सीबीआई का सारा प्रयास इसी बात पर रहता है कि कोई भी कथित अभियुक्त मामले को प्रभावित न कर पाये। इस मामले में अधिकारी के प्रभाव के सारे प्रमाण सामने हैं। ऐसे में सीबीआई प्रबोध सक्सेना की जमानत रद्द करवाने पर विचार करने को बाध्य हो गयी है। क्योंकि सबकी नजरें अब इस मामले पर लग गयी हैं।

चुनाव घोषणा पत्र से पहले ही चुनावी वायदों का औचित्य सवालों में

क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शीत युद्ध शुरू है

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस का आरोप पत्र जितना लेट होता जा रहा है उस अनुपात में पार्टी के बड़े नेताओं में वैचारिक विरोधाभास मुखर होता जा रहा है। सरकार को मुद्दों पर घेरने के बजाय कुछ नेता अपने अपने तौर पर ही एक तरह से चुनावी वायदे करने पर आ गये हैं। यह स्वभाविक हैं कि राजनीतिक दल चुनाव में उतरने के लिये जनता से वायदे करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किये थे जिनको बाद में जुमलो की संज्ञा दी गई थी। आज हिमाचल लगातार कर्ज के चक्रव्यू में घंसता जा रहा है। जयराम इस स्थिति के लिये कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से इसका कोई प्रमाणिक जवाब नहीं आ रहा है। बल्कि कांग्रेस नेता स्वयं ऐसी घोषणा करते जा रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ेगा या फिर जनता पर करों का बोझ लादना पड़ेगा। जबकि यह दोनों स्थितियां प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए घातक होंगी।

अभी यह वायदा किया गया है कि हर महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। युवाओं के लिये 680 करोड़ की युवा स्टार्टअप योजना शुरू की जायेगी। शिक्षा और बागवानी में दो लाख नौकरियां दी जायेंगी। बागवानी कमीशन का गठन किया जायेगा और पैकेजिंग मैटेरियल पर जीएसटी समाप्त कर दिया जायेगा। अभी तक शायद चुनाव घोषणापत्र तैयार करने वाली कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन घोषित वायदों पर कितने लोगों की सहमति बन पायी है। इन वायदों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन क्या होंगे और कहां से आयेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह जो वायदे किये जा रहे हैं यह सब एक तरह से मुफ्त खोरी की श्रेणी में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक ने इन मुफ्तखोरी योजनाओं का कड़ा संज्ञान लिया है और यह माना जा रहा है कि इन चुनावों से पहले इस संद्धर्भ में शीर्ष अदालत का कोई चाबुक चल सकता है ऐसे में इस तरह से घोषित की जा रही योजनाओं की व्यवहारिकता पर जब सवाल उठेंगे तो उनका जवाब देना कठिन हो जायेगा।

ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऐसे कर क्यों रहा है? क्या सही में कांग्रेस के पास इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आर्थिकी के इन पक्षों को समझता हो? क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी से मुख्यमंत्री पद के लिये अंदर खाते टकराव के हालात पैदा होते जा रहे हैं? इन सारे सवालों पर विचार करने के लिये यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार सरकार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप ही रहते आये हैं। इसके बाद कर्मचारी नेतृत्व भी दावा करता रहा है कि वह सरकारों के बनाने में बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन इसका एक सच यह भी है कि आज तक कर्मचारियों में से केवल दो नेता ही विधानसभा पहुंच पाये हैं। इसके बाद जातीय समीकरण प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं और संयोगवश डॉ. परमार से लेकर जयराम ठाकुर तक एक शान्ता कुमार को छोड़कर मुख्यमंत्री राजपूत वर्ग से ही बनता रहा है। भाजपा में तो संगठन का नेतृत्व भी अधिकांश में ब्राह्मण और राजपूतों में से ही रहा है। सुरेश कश्यप पहली बार अपवाद हैं। कांग्रेस में सभी वर्गो से संगठन का नेतृत्व रहा है। इस परिपेक्ष में आज कांग्रेस के अंदर सबसे वरिष्ठ ठाकुर कौल सिंह हैं उनके बाद प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू सब की राजनीतिक वरियता लगभग बराबर है। ऐसे में अभी कांग्रेस नेतृत्व को एकजुटता का परिचय देते हुये अपने राजनीतिक विरोधाभासों को विराम देकर चुनावी रण में उतरना होगा।

शेष

पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाएं विद्यार्थी:आर्लेकर

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे पाठय पुस्तकों के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकें पढ़ने का संकल्प लें। उन्होंने विद्यार्थियों को, उन्हें पत्र लिखकर पुस्तक पढ़ने के अपने अनुभव साझा करने को भी कहा।

राज्यपाल मण्डी जिला के थुनाग उप–मण्डल के लम्बाथाच में राजकीय डिग्री कॉलेज सराज के 12वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कॉलेज में हम विशिष्ट संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता के रूप में होना चाहिए। इस उद्देश्य से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और यही भविष्य की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम और स्टार्टअप आरम्भ किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का वार्षिक समारोह विचारों के आदान–प्रदान का अवसर प्रदान करता है। इसलिए इन्हें 'स्नेह सम्मेलन' भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय ने अपने अस्तित्व की अल्पावधि में व्यापक प्रगति की है, जिसके लिए प्रबंधन बधाई का पात्र है।

आर्लेकर ने कहा कि महाविद्यालय संस्कृति का प्रतीक है। शिक्षा के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं और किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं, यह महाविद्यालय हमसे तय करवाता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक जीवन का यह पड़ाव व्यक्ति के जीवन में सबसे यादगार समय होता है, जो जीवनभर याद रहता है। उन्होंने इस अवसर पर अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए उस समय के अनुभव विद्यार्थियों के साथ सांझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने माता–पिता के योगदान को हमेशा स्मरण रखने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने कहा कि देश अपनी आजादी का 75वां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री ने 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान का आहवान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे स्वयं भी इस अभियान में शामिल हों और अन्यों को भी प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को देश व समाज के बारे में विचार करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही विचार देश का भविष्य तय करता है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर राष्ट्रहित में काम करने की जरूरत है। इसके लिए इतिहास को जानें और पुस्तकें पढें। उन्होंने कहा कि सुविधाएं आप के पास हैं उनका उपयोग करें।

राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों एवं शैक्षणिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। वर्ष 2019–20 के लिए सराज गौरव का पुरस्कार दिव्या भारती तथा वर्ष 2020–21 के लिए कुशाल चंद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

इससे पूर्व, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राकेश शर्मा, ने राज्यपाल को सम्मानित किया तथा कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी।

इस अवसर पर सराज थियेटर ग्रुप ने अपनी प्रस्तुति दी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, मण्डी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, सरदार पटेल विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रो. अनुपमा सिंह तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किसान–वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मण्डी जिला के थुनाग में डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती किसान मेला और किसान–वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों के अनुभव प्रेरणादायी हैं और इन अनुभवों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में प्राकृतिक खेती और इसके उत्पादों के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाने में पहल करते हुए पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और प्रत्येक प्रगतिशील किसान को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों को इस पद्धति को और विस्तार देने के लिए आपस में सहयोग करना होगा।

भारतीय रेड क्रॉस प्रबन्धन समिति की सदस्य और राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर ने प्राकृतिक खेती अभियान में योगदान का आग्रह किया।

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चन्देल ने कहा कि हिमाचल पूरे देश का अगुवा बनते हुए प्रथम प्राकृतिक खेती राज्य बना है और पूरे प्रदेश में सराज विधानसभा क्षेत्र प्राकृतिक खेती को पूर्ण रूप से अपनाने में तेजी से अग्रसर हिमाचल का पहला विधानसभा क्षेत्र बन गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जगदीप धनखड़ के व्यापक अनुभव से राष्ट्र निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जगदीप धनखड़ लोकतंत्र के मूल्यों को और सुदृढ़ करने में देश का मार्गदर्शन करेंगे।

राज्यपाल ने जिला मंडी की झुंडी पंचायत से हरियाली पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला मंडी के थुनाग उपमंडल के अन्तर्गत झुंडी पंचायत के बड़ा मैदान में टैक्सस बक्काटा (थून) का पौधा रोपित कर हरियाली पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर उपस्थित थी। डॉ. साधना ठाकुर ने देवदार का पौधा भी रोपित किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से प्रदेश भर में हरियाली पौध रोपण अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में एक दिन में एक लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है और केवल मंडी जिला में 12000 पौधे रोपित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाएगा और वन विभाग द्वारा इस अभियान के लिए पौधे उपलब्ध करवाएं जाएंगे। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी नाचन तीर्थ राम धीमान ने राज्यपाल को शॉल और हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित किया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी के सहयोग से थुनाग में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारम्भ भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाया जा सके।

इस अवसर पर राज्यपाल ने गरीब और पात्र व्यक्तियों को 10 व्हील चेयर, 2 बैसाखियां और एक वॉकिंग स्टिक भेंट की। जिला रेड क्रॉस सोसायटी मंडी द्वारा अब तक पात्र व्यक्तियों को 137 व्हील चेयर और 71 बैसाखियां एवं वाकिंग स्टिक वितरित की जा चुकी हैं।

राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेड क्रॉस के महासचिव राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेन्द्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

मुख्यमंत्री ने पहलवानों को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों–2022 में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों रवि दहिया, विनेश फोगट और नवीन मलिक को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पहलवानों की इस उपलब्धि से देश के अन्य खिलाड़ियों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।

हर घर तिरंगा अभियान: स्वतंत्रता दिवस तक सभी दिन खुले रहेंगे डाकघर

शिमला/शैल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री और वितरण की सुविधा के लिए, सभी डाकघर स्वतंत्रता दिवस 2022 से पहले छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे। देश भर में सभी डिलीवरी डाकघर और अन्य महत्वपूर्ण डाकघर इस सार्वजनिक अभियान का समर्थन करने के लिए खुले रहेंगे।

सार्वजनिक छुट्टी के दिनों अर्थात 7, 9 और 14 अगस्त 2022 को डाकघरों में कम से कम एक काउंटर के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। सभी डिलीवरी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज के वितरण की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमुडा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका ऊना जिला के अम्ब में निधन हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवीण शर्मा एक ईमानदार और समर्पित नेता थे जो सदैव जनता के लिए समर्पित रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को प्रदेशवासियों द्वारा सदैव याद रखा जाएगा।

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में देश का पहला राज्य बना हिमाचलः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि 15 अप्रैल 1948 को स्थापना के बाद हिमाचल प्रदेश ने 75 वर्षो के दौरान बहुत तेजी से प्रगति की है। हिमाचल की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर शिमला के रिज मैदान में आयोजित 'प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष' समारोह के अवसर पर भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बाद राज्य ने विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की गौरवशाली विकास यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आये, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इस गौरवशाली सफर के बारे में आम लोगों को जागरुक करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 75 कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि इन वर्षो के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रदेश के मेहनती लोगों और सभी सरकारों के सक्षम नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश में 228 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, जबकि आज राज्य में 39,500 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें हैं। 75 वर्ष पहले राज्य में केवल 301 शैक्षणिक और 88 स्वास्थ्य संस्थान थे, जबकि आज राज्य में 16,124 शैक्षणिक और 4320 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार ने राज्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी और उन्होंने सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हिमाचल के दुर्गम इलाकों को सड़कों से जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में लगभग 50 प्रतिशत सड़कों का निर्माण इसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में हिमाचल देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में एम्स, आईआईएम, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 90:10 के अनुपात को बहाल करने के अलावा राज्य को 800 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी प्रदान की है।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इन 75 वर्षो के दौरान प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश में हुई प्रगति से हिमाचल प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 1948 में केवल कुछ घरों में ही बिजली उपलब्ध थी, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और प्रदेश एक ऊर्जा सरप्लस राज्य बन गया है।

इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्मित हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पर एक थीम गीत और हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षो के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। समारोह में हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, सक्षम गुड़िया बोर्ड की अध्यक्ष रूपा शर्मा, शिमला मंडल के भाजपा अध्यक्ष राजेश शारदा, प्रधान सचिव भरत खेड़ा और सुभासीष पन्डा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका, निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने जीवनधारा श्रवण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से जीवनधारा-श्रवण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला के माध्यम से शुरू किया गया यह वाहन श्रवण संबंधी समस्या की शुरुआती जांच और स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 70 लाख रुपये का यह वाहन अत्याधुनिक उपकरण जैसे ऑडियो मीटर, ऑटो एकोस्टिक ऐमिशन तथा बैरा इत्यादि से लैस है। इस वाहन में वाहन चालक सहित दो तकनीशियन और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह वाहन प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य खण्डों व अस्पतालों में भेजा जाएगा जहां श्रवण संबंधी समस्या से ग्रसित मरीजों की जांच की जाएगी। इस वाहन में लगे उपकरण के माध्यम से मरीजों की जांच कर उन्हें हियरिंग एड ऑपरेशन और उपचार के लिए उपयुक्त संस्थानों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वाहन के माध्यम से बुजुर्गो में सुनने की मशीन व बच्चों में ऑपरेशन तथा कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने में भी सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निरोग योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के कानों की वार्षिक जांच का प्रावधान है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक महत्वकांक्षी कदम उठाए गए हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बागवानों के साथ बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सभी बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव आर.डी. धीमान

की अध्यक्षता में प्रगतिशील बागवानों और सम्बन्धित सचिवों एवं विभागाध्याक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें बागवानों के हितों और सेब की फसल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021 में प्रापण किए गए सेब की लम्बित राशि 8.59 करोड़ रूपये में से 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ रूपये हिमफैड को 30 जुलाई, 2022 को जारी कर दिए हैं तथा प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफैड को आदेश दिए गए हैं कि वे बागवानों की लम्बित राशि नगद में एक सप्ताह के भीतर जारी करना सुनिश्चित करें।

प्रवक्ता ने बताया कि बागवानी नीति में बदलाव करते हुए प्रदेश सरकार ने गत वर्षो की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

उन्होंने बताया कि बागवानों से सम्बन्धित उपकरण, एंटीहेल्नेट तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग को 20 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं जिसे सम्बन्धित जिलों को आबंटित कर दिया गया है। जैसे ही इस राशि को व्यय कर लिया जाएगा, उसके तत्पश्चात अतिरिक्त बजट के प्रावधान करने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी।

प्रदेश के सभी निजी सी.ए. स्टोर में लिए जाने वाले सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए डा.वाई एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवानों को भी शामिल किया गया है ताकि सेब के दामों को तय करने की प्रकिया में पारदर्शिता लाई जा सके।

प्रदेश में सभी निजी सी.ए.स्टोर में बागवानों के सेब रखने के प्रावधान को समझौता ज्ञापन के अनुसार सख्ती से लागू करने के लिए उद्यान विभाग को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में बागवानी विकास के लिए बागवानी बोर्ड स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति में है।

बागवानों को फल प्रसंस्करण इकाई व सी.ए. स्टोर स्थापित करने के लिए बागवानी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त फल प्रसंस्करण इकाई एवं सी.ए. स्टोर स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण राज्य मिशन के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

प्रवक्ता ने सभी किसानों , बागवानों, पंचायत समितियों, सहकारी समितियों से उन्होंने आग्रह किया कि वे सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित करके उक्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी बागवानों को पहली अप्रैल, 2022 के बाद एचपीएमसी या खुले बाजार से सेब कार्टन एवं ट्रे करने पर उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 6 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। यह उपदान बागवानी विभाग एवं एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। बागवान अपने नजदीकी उद्यान विभाग अथवा एचपीएमसी के कार्यालय में जाकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि 6 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) का लाभ अथवा उपदान सीधा बागवान के खाते में 15 दिनों के भीतर जमा कर दिया जाएगा।

किसानों और बागवानों द्वारा उठाई गई मांगों पर विस्तृत चर्चा के लिए बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के प्रगतिशील बागवानों को भी आमंत्रित किया गया था।

बैठक में एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, सुशांत देष्टा, पवन चौहान, विशाल चौहान और चेतन बरागटा ने भाग लिया।

नशे की समस्या से निपटने के लिये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 26 जून को एडीजीपी सीआईडी की अध्यक्षता में एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी जो यह टास्क फोर्स हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 29 जुलाई को अधिसूचित कर दी गई है।

इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या से समग्र रूप से निपटना है। यह हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों और सरकार के अन्य विभागों के साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर काम करती है।

इसके अलावा ANTF राज्य में सक्रिय बड़े-बड़े नशा माफियाओं पर लगाम लगाने का काम भी कर रही है। इसी कड़ी में ANTF द्वारा प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्निफर डॉग स्क्वायड के साथ लगातार चेकिंग की जा रही है और लोगों द्वारा दी गई सूचनाओं पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही भी कर रही है। इनमे शिमला यूनिट द्वारा सनवारा टोल पर चेकिंग के दौरान हेरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आईजीएमसी के पास दो केमिस्ट के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की गई है।

कुल्लू यूनिट ने मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर दो अनाधिकृत केमिस्ट शॉप पर कार्यवाही की और सभी दवाइयां भी जब्त की। कुल्लू यूनिट ने हेरोइन तस्करी और कुरियर/पोस्ट के माध्यम से चरस तस्करी करने वालों को भी गिरफ्तार किया है। कांगड़ा यूनिट ने भी कई हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

ANTF ने सोशल मीडिया पर लोगों से सूचनाएं और जानकारी साझा करने के लिए अपने नए ट्विटर (@antf-hp) और इंस्टाग्राम (@antf-hp) हैंडल्स भी बनाए हैं। ANTF का फेसबुक हैंडल (https://www.facebook.com/antfhp) है। सभी लोग इन हैंडल्स पर हमारी अपडेट्स को देख सकते हैं।

इसके साथ ही लोग हमें 'ड्रग फ्री हिमाचल ऐप' के माध्यम से गोपनीय तरीके से नशा तस्करों की सूचनाएं भी दे सकते हैं।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 14446 जारी की है जिसके माध्यम से नशे की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद की जा रही है और नशे के खिलाफ जागरूकता भी लाई जा रही है। ANTF आप सभी लोगों से हमारी इस मुहिम में जुड़कर नशे के खिलाफ लडाई में अपना सहयोग देने का अनुरोध करती है।

जो मनुष्य अपने समय से आगे का विचार करता है, लोग उसे गलत समझते है।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

बढ़ती महंगाई बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था में....

पिछले दिनों जब सरकार ने सामान्य खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी लगा दिया था तब से महंगाई और बेरोजगारी देश में एक प्रमुख मुद्दा बनकर चर्चा का केंद्र बन गयी है। जीएसटी के फैसले के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती योजनाओं पर चिंता व्यक्त की है। बल्कि प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार चुनाव आयोग नीति आयोग और राजनीतिक दलों से भी उनकी राय पूछी है। संसद में महंगाई बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के बढ़ते दुरुपयोग पर विपक्ष लगातार बहस की मांग करता आ रहा है। लेकिन सरकार बहस को टालती आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता के बाद संसद में भाजपा के सुशील मोदी मुफ्तखोरी की योजना पर एक प्रस्ताव लेकर आये और इस प्रस्ताव में जिस तरह से प्रतिक्रिया भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ही व्यक्त की है वही अपने में बहुत कुछ कह जाती है। वरुण का यह सवाल कि क्या चर्चा करने वाले सबसे पहले अपनी ही सुविधाओं में कमी करने को तैयार होंगे। विधायकों सांसदों को मिलने वाली पैंशन और अन्य सुविधाएं एक अरसे से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विधान सभाओं और संसद को अपराधियों से मुक्त करने का प्रधानमंत्री का वायदा अभी तक अमली शक्ल नहीं ले पाया है। जबकि आज आर बी आई कर्ज की ब्याज दरें बढ़ाने को बाध्य हो गया है। आज स्थिति उस मोड़ तक आ चुकी है जहां हर समझदार व्यक्ति यह आशंका व्यक्त करने लग गया है कि देश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह प्रधानमंत्री को इस बारे में सचेत कर चुके हैं। आरबीआई उन राज्यों की सूची जारी कर चुका है जो श्रीलंका होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार गिरावट के कारण विदेशी निवेशक अपना निवेश बाजार से निकालते जा रहे हैं। लेकिन सरकार तथ्यों के विपरीत जनता को अर्थव्यवस्था के प्रति आश्वस्त करने का जितना प्रयास कर रही है उसी अनुपात में इस पर सवाल पूछने वाले सांसदों का निलंबन और राजनीतिक दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बढ़ाती जा रही है। जांच एजेंसियों पर अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बजाये सरकार के हाथों खिलौना बनने का आरोप ज्यादा लग रहा है। क्योंकि ईडी की जांच उन्हीं लोगों के खिलाफ हो रही है जो सरकार से सवाल पूछने का साहस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह सामने आ चुका है कि एक जैन के यहां छापा मारकर कैश की बरामदगी जब हुई और यह पता चला कि यह जैन तो भाजपा का समर्थक है तो इस मामले को आयकर का मामला बताकर रफा–दफा कर दिया गया। उसके बाद सपा के समर्थक एक अन्य जैन के यहां छापेमारी की गयी और मामला बनाया गया। यही स्थिति आज हेराल्ड मामले में हो रही है। ए जे सैक्शन 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है और इस नाते ईडी के दायरे से बाहर है। विधि विशेषज्ञ लगातार यह कह रहे हैं लेकिन ई डी इसका जवाब ही नहीं दे रही है। ई डी ने जब यह सवाल पूछा कि आप हेराल्ड को जिंदा क्यों करना चाहते हैं तब यह सारा कुछ स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को निष्पक्ष मीडिया मंच के आने से कष्ट हो रहा है।

ऐसे दर्जनों मामले हैं जिन से यह प्रमाणित हो जाता है कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां राज्यों से लेकर केंद्र तक सरकार के हाथों में कठपुतली बनकर काम कर रही हैं। इस परिदृश्य में अहम सवाल हो जाता है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। इस समय वित्तीय स्थिति के कुछ आंकड़ों को यदि ध्यान में रखा जाये तो इसे समझना आसान हो जायेगा। बैंकों में आम आदमी के हर तरह के जमा पर 2014 के बाद से लगातार ब्याज दरें क्यों कम होती जा रही हैं? 2014 में जो विदेशी कर्ज 54 हजार करोड़ था वह अप्रैल 2022 तक 1,30,000 करोड़ कैसे हो गया? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 18.50 लाख करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में क्यों बांटा गया? इसके लाभार्थी कौन हैं? इसमें से क्या कोई पैसा वापस आया है? इसी संसद सत्र में यह जानकारी आयी है कि बैंकों का दस लाख करोड़ राइट ऑफ किया गया? एनपीए के लिये बैड बैंक बनाने की नौबत क्यों आयी? आज 5G स्पैक्ट्रम रिजर्व कीमत से भी कम पर क्यों बेच दिया गया? यह कुछ सामान्य और मोटे स्वाल हैं जिन पर निष्पक्षता के साथ विचार करने पर देश की वित्तीय स्थिति और आम आदमी पर उसका महंगाई तथा बेरोजगारी के माध्यम से पड़ने वाला प्रभाव समझ आ जायेगा। आम आदमी को जिस दिन यह समझ आ जायेगा तब उसके पास सड़क पर निकलने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जायेगा। इसलिये इस सब से बचने के लिये जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के अतिरिक्त और कोई साधन सरकार के पास नहीं बचा है।

नशे से आजादी–राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम

शिमला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान नाम का एक प्रमुख अभियान चला रहा है, जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 2020 को भारत के 272 जिलों में किया गया था। जैसा कि हमारा देश इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 4 अगस्त 2022 को 'नशे से आजादी' –राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में किया गया और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 75 विश्वविद्यालयों और लगभग 700 संस्थानों ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उनके कुलपति, संकाय सदस्य और चिन्हित किए गए विश्वविद्यालयों/संस्थानों के छात्रा शामिल थे।

अपने मुख्य भाषण में, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थो का सेवन संबंधी विकार एक गंभीर समस्या है जो देश के सामाजिक ताने–बाने को प्रतिकूल से प्रभावित कर रही है। किसी भी मादक पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। भारत को नशीली दवाओं के प्रति संवेदनशील बनाना सरकार के साथ–साथ समुदाय और व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी है। नशामुक्त भारत अभियान लगभग दो साल पहले 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और समुदाय की एक ऐसी सेना तैयार करना था जो आत्मनिर्भर और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों से अच्छी तरह से अवगत हो। नुक्कड़ नाटकों, साइकिल रैलियों, प्रतियोगिताओं और दीवार पर चित्रों के रूप में अपने अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान ने मौजूदा सामाजिक सोच को बदला है और एक क्रांति लाई है।

इस क्रांति को और अधिक ऊर्जा मिलनी चाहिए और एक ऐसी जागरूकता पैदा करनी चाहिए जो उन लोगों को रोशनी दिखाए जो मादक द्रव्यों के सेवन के विकारों से प्रभावित हैं। नशामुक्त भारत अभियान के तहत, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी को बिना किसी भेदभाव और कलंक के इलाज एवं पुनर्वास और बेहतरी के लिए एक समावेशी वातावरण मिले। मादक द्रव्यों के सेवन की इस सामाजिक समस्या को पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से हमारे देश के ताने–बाने

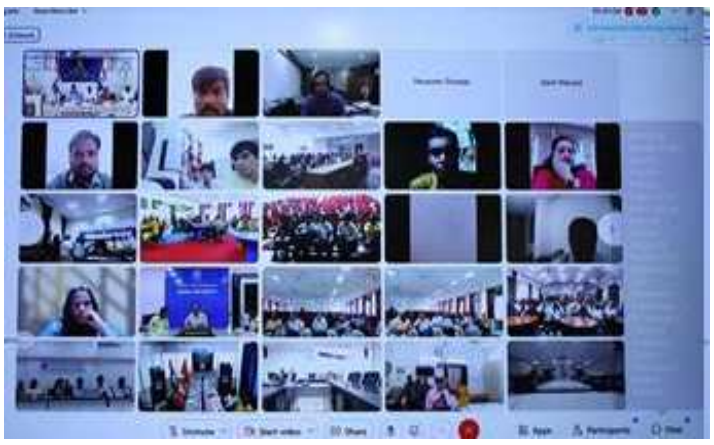

में बुना गया है और इसे जनसंचार के चैनलों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया है, जिसने इसको प्रभावित आबादी की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील बना दिया है। अक्सर यह कहा जाता है कि सामाजिक समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं जहां सामूहिक प्रयास से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस अभियान के माध्यम से उठाए अपने हर कदम के साथ हम सामूहिक प्रयास से इस सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। सभी को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ एकजुट होना चाहिए और मादक पदार्थो के उपयोग के प्रति एक जागरूक भारत के भविष्य में विश्वास करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में प्रधान सचिव प्रतीक हजेला द्वारा ''एनएमबीए के तहत प्रशासन कैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ा'' के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में नशीली दवाओं के उपयोग और इसके प्रभाव से उत्पन्न चुनौती से निपटने के तौर–तरीकों को प्रदर्शित किया गया था।

इसके बाद, देश के सभी चार क्षेत्रों के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने विचारों को साझा किया और इस अभियान के तहत उनके द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कुछ छात्रों और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से उबरने वालों के साथ बातचीत भी की। इन छात्रों ने एनएमबीए के तहत अपने संस्थानों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में लगभग एक लाख छात्रों ने भाग लिया।

इन 75 विश्वविद्यालयों और उनके अधीन आने वाले लगभग 700 संस्थानों ने 04.08.2022 को दिन भर ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए।

राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की गई

शिमला। अनुसंधान क्षमताओं को संरचित तरीके से बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई थी ताकि राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अलावा इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्यरत स्ववित्तीय संस्थानों में एक मजबूत आरएंडडी इकोसिस्टम बनाया जा सके।

स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस (एसईआरबी–एसयूआरई) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की एक नई अभिनव योजना है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का एक वैधानिक निकाय है। यह राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

एसईआरबी के अध्यक्ष और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी) विभाग के सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा,'नई योजना विश्वविद्यालय प्रणाली को मुख्य अनुसंधान में लाने में मदद करेगी और वहां के युवा संकाय को अत्याधुनिक अनुसंधान में भाग लेने में सक्षम बनाएगी जो अब तक ज्यादातर शिक्षण तक ही सीमित थी।' उन्होंने कहा कि नया कार्यक्रम, जो डेटा–संचालित सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का भी समर्थन करेगा, हमारे विश्वविद्यालयों में अंतर्निहित क्षमता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों के संकायों को बहुत आवश्यक अनुसंधान अवसर प्रदान करेगी, जिनमें से 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्होंने परियोजनाओं के प्रस्तावों, खरीद और प्रबंधन के बारे में लिखने और प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालयों के संकाय को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के.एन.व्यास ने कहा, 'चूंकि बड़ी संख्या में राज्य विश्वविद्यालय ग्रामीण पृष्ठभूमि में हैं, वे जमीनी स्तर के अनुसंधान में भी भाग ले सकते हैं जिससे स्थानीय उद्योग और स्थानीय किसानों को लाभ होगा और जमीनी स्तर की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान की आवश्यकता होगी।'

एसईआरबी के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा ने कहा, 'इस योजना में, राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के वित्तपोषण को सुरक्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता होगी, और राज्य शोध क्षमताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करने के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर पेश करेंगे।'

इन संस्थानों में मौजूदा अनुसंधान क्षमताओं का विकास अनिवार्य है ताकि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में योगदान की उम्मीद कर रहे सभी शोध छात्रों तक अनुसंधान उत्कृष्टता का क्षैतिज प्रसार सुनिश्चित हो सके। इससे वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने और एसईआरबी समर्थन के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि को बढ़ावा मिल सकेगा।

एसईआरबी–एसयूआरई योजना विज्ञान, इंजीनियरिंग और मात्रात्मक सामाजिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए, भारत भर में इन विश्वविद्यालयों के भीतर काम कर रहे स्व–वित्तपोषित संस्थानों सहित राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संबंधित सक्रिय शोधकर्ताओं को अनुसंधान सहायता प्रदान करती है।

4.15 लाख बागवानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण में आत्मनिर्भर होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नगर निकाय प्रशासन जैसे मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में 1010 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है और मशरूम की खेती विशेषकर शिटाके और ढींगरी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गत साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश के 31,584 बागवानों को राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कवर किया गया है, जबकि 4.15 लाख बागवानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 3590 ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत लाया गया है और किसानों ने रासायनिक खाद के जगह प्राकृतिक खाद को अपनाकर लगभग 9.75 करोड़ रुपये की बचत की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्पाद बेचने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा प्रदेश भर में 10 विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक की मदद से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से हाल ही में घोषित स्वयं प्रभा के तहत कुल 200 चैनलों में से हिमाचल प्रदेश को 5 टीवी चैनल आवंटित करने का आग्रह किया। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात शत- प्रतिशत है जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में यह 85.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 98.8 प्रतिशत हो जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा एवं निःशुल्क आवासीय सुविधा के अलावा कौशल शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा डेटाबेस का डिजिटिकरण किया जा रहा है और डिजिटल मोड में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षकों की क्षमता का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों तक छात्रों की आसानी से पहुंच है और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। जिला मण्डी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को अप्रैल, 2022 से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में राज्य का सकल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 40.8 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति की राशि, लड़कियों और लड़कों की श्रेष्ठता छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती सुपर 100

योजना के अलावा प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं के इच्छुक मेधावी छात्रों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राज्य सरकार शोधार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्लेसमेंट सेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ड्रोन नीति बनाई गई है और राज्य में आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग के लिए छात्रों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक पदों को भरकर शहरी निकायों के प्रशासन को सुदृढ़ करने और नवीनतम तकनीक की मदद से लोगों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं देने की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआईएस मैपिंग का उपयोग संपत्ति कर के आकलन और संग्रह के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता शुल्क के निपटान और अन्य नगर परिषद सेवाओं के लिए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए एकल सदस्य नगरपालिका सेवा नियामक समिति का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर. डी. धीमान भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करना ही तिरंगे की ताकत है:अनुराग ठाकुर

शिमला। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में लाल किले से इंडिया गेट तक सांसदों की 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'हर घर तिरंगा' की जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सांसदों ने हिस्सा लिया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्यक्रम के दौरान बाइक की सवारी की। श्री ठाकुर ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्री, सांसद और युवा नेता एक साथ आए हैं। संदेश ये कि हम सब अपने देश को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को मजबूत बनाएंगे। 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करना ही तिरंगे की ताकत है। आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं, और आजादी का अमृत महोत्सव में ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने और भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

'हर घर तिरंगा' अभियान भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों और राष्ट्रीय ध्वज के बीच एक व्यक्तिगत जुड़ाव पैदा करने की एक पहल है। इसका मकसद लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय उत्साह की भावना को मजबूत करना है ताकि वे जनभागीदारी की भावना से लबरेज होकर आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लें।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना ने महिलाओं के लिए खोले उद्यमिता व आत्मनिर्भरता के द्वार

योजना के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं ने स्थापित की 1969 इकाइयां

शिमला। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं। उनके बिना उन्नत समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रारम्भ की गई सरकार की योजनाओं का सुपरिणाम है कि आज पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ ही महिलाओं के उद्यमिता की ओर कदम आगे बढ़ाए हैं। बैंकिंग, शिक्षा सहित अन्य पारम्परिक क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर महिलाओं ने उद्यमिता जैसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई हैं।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना उद्यमिता क्षेत्र में भविष्य बनाने के महिलाओं के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली आर्थिक मदद से महिलाएं आज अपने व्यवसाय स्थापित कर पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहीं हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और प्रदेश के युवाओं को वे रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही हैं।

इस योजना से रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए जहां पुरूषों को 25 प्रतिशत का निवेश उपदान प्रदान किया जाता है, वहीं महिलाओं के लिए यह दर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है। योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत की दर से तीन वर्षों तक ब्याज उपदान भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के पुरूष तथा 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग की महिलाएं पात्र हैं।

योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 4377 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं तथा 200 करोड़ रुपये उपदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। योजना के अन्तर्गत 1969 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य में बैंकों द्वारा कुल 6927 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला की 273, सोलन जिला की 236, ऊना ज़िला की 215, मण्डी ज़िला की 209, सिरमौर ज़िला की 200, हमीरपुर ज़िला की 194, शिमला ज़िला की 184, बिलासपुर ज़िला की 171, कुल्लू ज़िला की 152, चम्बा ज़िला की 61, किन्नौर ज़िला की 48 और लाहौल-स्पिति जिला की 26 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। यह योजना कम लागत वाले स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहन देते हुए सामाजिक उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

सकारात्मक परिणाम सामने आने पर राज्य सरकार ने इस योजना को विस्तार प्रदान करते हुए वर्ष 2021 में इसमें नए व्यवसाय शामिल किए हैं। इनमें डेयरी, कृषि आधारित पर्यटन, कृषि उपकरण निर्माण, सब्जी नर्सरी, पैट्रोल पम्प, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस सेवा व रेशम प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का लाभ उठाकर महिलाएं सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। कुल्लू जिला के भुंतर की निवासी सुरूचि भानु अपने भाई के साथ इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। उन्होंने 2021 में जिम खोलने के लिए लगभग 40 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया। आज उनके जिम में 51 युवा शारीरिक फिटनेस ट्रेनिंग की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से कुछ युवा पुलिस बल और सेना में भर्ती होने की तैयारियां कर रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए दो प्रशिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह इस व्यवसाय से डेढ़ लाख रुपये तक की आय अर्जित हो जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना स्वरोजगार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जिससे प्रदेश के हजारों युवा लाभान्वित हो रहे हैं।

जिला मंडी के रत्ती, नेरचौक की संजना शर्मा भी मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ी है। उनका परिवार लंबे समय से बेंगलुरू में बसा हुआ था। संजना शर्मा स्वयं शिक्षिका और डाइटिशन के रूप में कार्य कर रही थीं, जबकि उनके पति इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। संजना अपनी आंखों में घर वापसी का सपना संजोए हुए थी जिसे पूरा करने में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आशा की किरण बनकर सामने आई।

संजना ने योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू करने की ठानी। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत अपना रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए उन्होंने 11.50 लाख रुपये का ऋण लिया। विभाग से उन्हें साढ़े तीन लाख रुपये का उपदान मिला। वर्तमान में वह रेस्टोरेंट से लगभग 80 हजार रुपये प्रतिमाह के आमदनी अर्जित कर रही है। इस रेस्टोरेंट में उन्होंने 11 लोगों को रोजगार प्रदान किया हैं, जिनमें तीन स्थानीय महिलाएं भी शामिल हैं। संजना शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह योजना महिलाओं की आत्मनिर्भरता की उड़ान को पंख लगा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं प्रदेश की आर्थिकी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी यह योजना मददगार साबित हो रही है।

इस योजना से महिलाओं के हुनर को नई पहचान मिल रही है। सफलता की ये कहानियां नवोदित महिला उद्यमियों का मार्गदर्शन कर रही हैं और हिमाचल की विकास गाथा में प्रदेश सरकार की नवोन्मेषी योजनाओं की भूमिका को भी सार्थक सिद्ध कर रही हैं। इस विकास गाथा में नित नए नाम जुड़ रहे हैं, जो प्रदेशवासियों के जीवन में आ रहे सुखद बदलाव और समृद्धि का बखान करती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। यह राज्य के विभिन्न संस्थानों में लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और ट्रे पर छः प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए कार्टन व ट्रे का जीएसटी भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक एकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा।

बैठक में उचित मूल्य के दुकान धारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा सात रुपये 57 पैसे से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर के 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला की तहसील घुमारवीं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटवाड़ को 10 बिस्तर क्षमता के स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलोखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में किन्नौर जिला की तहसील कल्पा के पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इस संस्थान के लिए तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला की तहसील थुनाग के शिकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ तीन पदों को सृजित कर भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाखड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ चार पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेहड़वीं और कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में किन्नौर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्पीलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कुल्लू जिला की आनी तहसील के थैरहवीं में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत आम्बल ठेहड़ू और ग्राम पंचायत भाली के गांव भाली में नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ छः पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के परवाणू में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इसमें विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जामली में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में सोलन जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़खल को 20 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस नव स्तरोन्नत संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के जाडला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतेहड़ गांव में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के तहत धुलेट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मंडयाल सभा सोलन को सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए सोलन तहसील के कोठों गांव में एक बीघा सरकारी भूमि 2,35,281 रुपये के वार्षिक पट्टे पर प्रति पांच वर्ष के बाद पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 30 वर्षों तक उपलब्ध करवाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने विवेकानंद केन्द्र नाभा एस्टेट शिमला को हर्बल गार्डन और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 1,54,647 रुपये के वार्षिक पट्टे पर प्रति पांच वर्ष के बाद पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30 वर्षों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक खंड कुल्लू-प्रथम के अंतर्गत कियाणी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिड़कमार, सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरुणा तथा हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने और प्रत्येक महाविद्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गांव कुठेड़ा बेला और गांव कैंट में नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने चंबा जिला में नव-स्वीकृत राजकीय स्नातक महाविद्यालय बनीखेत में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला के नेरचौक में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में किए गए निर्माण को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति मंडल झंडूता के तहत तलाई में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल घुमारवीं के अंतर्गत बहेड़ में कनिष्ठ अभियंता अनुभाग और कपाहड़ा में एक अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जल शक्ति मंडल नगरोटा बगवां के अंतर्गत कंडी में नया अनुभाग खोलने तथा इसके लिए 4 पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का नया मॉडल कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कनोला उपरला स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर, टेक्निकल मेकाट्रॉनिक्स, मेकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नये ट्रेड आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (महिला) कंडाघाट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठयक्रम और कांगड़ा जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तलवाड़ में फॉर्मेसी में डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में नया उप-अग्निशमन केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर भरने के अलावा, इस उप-अग्निशमन केंद्र के लिए 3 दमकल वाहन खरीदने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शहीदों के सम्मान में सिरमौर जिले के राजकीय उच्च पाठशाला कोटरी ब्यास का नाम बदलकर शहीद कमल कांत मेमोरियल राजकीय उच्च पाठशाला कोटरी ब्यास, राजकीय उच्च पाठशाला सुनोग का नाम शहीद रविंदर सिंह चौहान राजकीय उच्च पाठशाला सुनोग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा का नाम शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानौर का नाम शहीद राजेन्द्र सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानौर रखने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, घरोह में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बोह एवं राजोल में विज्ञान (नॉन-मेडिकल) की कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय सरार, पुखरी, कदेड़, रान, भराड़ा और कांडला, मण्डी जिले के राजकीय उच्च विद्यालय, मंजखेतर, कांगड़ा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय, गगवाल और हमीरपुर में राजकीय उच्च विद्यालय पनसाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और चम्बा जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय झौरा, प्रियुंगल, करोरी, मंगली, अनियुंडा, सारंगेर, औला और बिहाली को राजकीय उच्च विद्यालय, कांगड़ा जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजा खास, मण्डी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पंजोलठ को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने एवं इन संस्थानों में आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों चेवा, कांडा, गइघाट और कक्कड़हट्टी में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, प्राथा, भोजनगर और कोटबेजा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने और इन शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

नौणी विश्वविद्यालय में डॉ वाईएस परमार को दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 116वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें प्रसिद्ध लोक कलाकार और लेखक पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री विद्यानंद सरैक मुख्य वक्ता रहे।

अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि हिमाचल के इस दूरदर्शी नेता के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण विवि के सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि डॉ. परमार ने प्रदेश में कृषि, बागवानी और वानिकी गतिविधियों के सतत विकास की वकालत कर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाए। डॉ.परमार के विभिन्न साहित्यिक कार्यों को पढ़ने का छात्रों से आग्रह करते हुए प्रो. चंदेल ने कहा कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब राज्य का प्रत्येक नागरिक डॉ. परमार के नक्शेकदम पर चले और पहाड़ी संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में योगदान दे।

इस अवसर पर श्री विद्यानंद सरैक ने कहा कि डॉ. परमार पहाड़ी लोगों के सच्चे हितैषी थे और राज्य के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने डॉ. परमार के साथ अपनी कई मुलाक़ात के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा लोक कलाकारों और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने जीवन के कई किस्से साझा किए और सभा को बताया कि कैसे वह स्थानीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए डॉ. परमार के ऋणी है। उन्होंने डॉ. परमार का पहाड़ी लोक संगीत के प्रति रुचि के बारे में भी बताया और सभी छात्रों से अपनी संस्कृति और विरासत को अपनाने और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में एक पौध भी लगाया और डॉ. परमार के जीवन की कई तस्वीरों का संग्रह देखने के लिए विश्वविद्यालय के परमार संग्रहालय का दौरा भी किया। इससे पूर्व डॉ. रविन्द्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. देवेन्द्र गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी वैधानिक अधिकारी, कर्मचारी और छात्रा उपस्थित रहे।

1. भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत घोषित मामलों के लिए यकमुश्त निपटान योजना 2021

(ONE TIME SETTLEMENT GUIDELINES FOR ALR LOANS, 2021)

इस योजना के तहत राष्ट्रीय निगमों (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के सौजन्य से वितरित किए गए मु0 0.50 लाख से अधिक के ऋण मामले जिनमें वर्तमान में भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया चल रही है शामिल हैं।

1. **पात्रता–** इस यकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत 31.3.2020 से पूर्व निगम द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत (ए.एल.आर) घोषित 274 ऋण मामले जिनमें वर्तमान में भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया जारी है पात्र होंगे।
2. **योजना की अवधि–** यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात लागू तिथि से 1 वर्ष अर्थात 29.01.2021 से 28.01.2022 तक मान्य होगी तथा एक वर्ष पश्चात स्वयं समाप्त हो जायेगी।
3. **यकमुश्त निपटान राशि–** इस योजना के अंतर्गत केवल भू–राजस्व (ए.एल.आर) के अंतर्गत घोषित बकाया राशि मु0 5.47 करोड़ रूपये वसूली की जायेगी तथा ए.एल.आर घोषित होने की तिथि के पश्चात लगाया गया ब्याज मु0 5.85 करोड व नकद हानि मु0 3.46 करोड़ रुपए माफ किया जाना है।
4. **यकमुश्त ऋण राशि का भुगतान–** इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को घोषित समस्त ए.एल.आर. राशि को अधिमानतः एक वर्ष के भीतर एक मुश्त जमा करना होगा। लाभार्थी 25 प्रतिश्त राशि एकमुश्त जमा कर शेष 75 प्रतिश्त राशि को योजना की अवधि तक बराबर त्रैमासिक किस्तों में वर्तमान ब्याज दर (साधारण ब्याज दर) सहित जमा कर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
5. **योजना के अंतर्गत प्रस्तावों का प्रसंस्करण–** लाभार्थी जो इस यकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं को निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित जिला प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक (विकास) के माध्यम से घोषित राशि का 10 प्रतिश्त अग्रिम सहित आवेदन करना होगा जिसे निगम मुख्यालय द्वारा निगम निदेशक मण्डल की अनुमति से दो माह के भीतर–भीतर प्रसंस्करण कर निपटान किया जाएगा।

2. मु0 0.50 लाख तक के पुराने व सूक्ष्म ऋण मामलों के लिये यकमुश्त निपटान योजना 2021

(ONE TIME SETTLEMENT GUIDELINES FOR SETTING OLD AND SMALL LOANS UPTO RS.050 LACS, 2021)

1. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा इस निगम के माध्यम से संचालित निम्न योजनाओं के अन्तर्गत मु0 0.50 लाख रुपए तक की ऋण राशि जारी की गई है। यकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत 13688 ऐसे ऋण मामले जो कि वित्तीय वर्ष 1980–81 से 2014–15 तक की अवधि में (23.01.2015) से पूर्व निगम द्वारा वितरित किए गए हैं लाभान्वित होंगे।

a. **मार्जिन मनी ऋण योजना–** इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वितरित ऋण मामलों में 25 प्रतिशत धनराशि सीमान्त धन के रूप में इस निगम द्वारा प्रदान की गई है कुल 1197 से ऋणियों से केवल 1.35 करोड़ रुपए मूलधन वसूल किया जाना है तथा ब्याज 1.70 करोड़ रुपए की राशि को माफ किया जाना है।

b. **हस्तशिल्प विकास योजना–** इस योजना के निगम के द्वारा ऋ ी को मु0 5000 का ऋण 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर शिल्पकारों को प्रदान किया गया है। कुल 120 ऋणियों के केवल मु0 0.47 करोड़ रुपए मूलधन वसूल किया जाना है तथा ब्याज मु0 0.10 करोड़ रुपए तथा ब्याज दण्ड ब्याज 0.01 करोड़ रुपए की राशि को माफ किया जाना है।

c. **सूक्ष्म वित्त पोषण/ अम्बेदकर लघु ऋण योजना–** इस योजना के तहत मूल्य 0.50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया गया है कुल 1595 ऋणियों से मूलधन 2.27 करोड़ रुपए वसूल किया जाना है तथा ब्याज मु0 0.67 करोड़, दण्ड ब्याज 0.33 करोड़ रूपये की राशि को माफ किया जाना है।

2. **पात्रता–** इस योजना में कुल 13668 लाभार्थी ही पात्र होंगे जिनसे कुल ऋण राशि का केवल मूलधन मु0 4.09 करोड़ रुपए ही वसूल कर शेष 2.47 करोड़ रूपये ब्याज तथा मु0 0.34 करोड़ रूपए दण्ड ब्याज माफ किया जाना है।
3. **योजना अवधि–** यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात लागू तिथि से 1 वर्ष अर्थात 29 .01. 2021 से 28 .01.2022 तक मान्य होगी तथा 1 वर्ष पश्चात स्वयं समाप्त हो जाएगी।
4. **यकमुश्त निपटान राशि–** इस योजना के अंतर्गत जो ऋणी यकमुश्त निपटान योजना की अवधि के भीतर–भीतर एक मुश्त में ऋण का निपटान करेगा उसे ब्याज तथा दण्ड ब्याज माफ किया जाएगा।
5. **यकमुश्त ऋण राशि का भुगतान–** इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कुल राशि अधिमानतः एक वर्ष के भीतर एकमुश्त जमा करना होगा। लाभार्थी 25प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कर शेष 75प्रतिशत राशि को योजना की अवधि तक बराबर त्रैमासिक किस्तों में वर्तमान ब्याज दर (साधारण ब्याज दर) सहित जमा कर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
6. **योजना के अंतर्गत प्रस्ताव का प्रसंस्करण–** लाभार्थी जो इस यकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं को नियमों के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (विकास) के माध्यम से घोषित राशि का 10 प्रतिशत अग्रिम सहित आवेदन करना होगा। जिसके अबिलम्ब निपटान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (विकास) को प्रधिकृत कर दिया गया है।

सम्पर्क कार्यालय

क्र. सं.	पदनाम	कोड नंबर	दूरभाष नंबर कार्यालय
	जिला कार्यालय		
1.	जिला प्रबन्धक सोलन	01792	223634
2.	जिला प्रबन्धक शिमला	01772	623917
3.	जिला प्रबन्धक नाहन (सिरमौर)	01702	222409
4.	जिला प्रबन्धक बिलासपुर	01978	222225
5.	जिला प्रबन्धक मंडी	01905	222127
6.	जिला प्रबन्धक कुल्लू	01902	222309
7.	जिला प्रबन्धक धर्मशाला (कांगड़ा)	01892	223108
8.	जिला प्रबन्धक चंबा	01899	222473
9.	जिला प्रबन्धक ऊना	01975	223694
10.	जिला प्रबन्धक हमीरपुर	01972	222402
11.	जिला प्रबन्धक किन्नौर (रिकांगपिओ)	01786	222302
12.	जिला प्रबन्धक लाहौल स्पिति (केलांग)	01900	222526
	सहायक प्रबन्धक कार्यालय		
13.	सह प्रबन्धक (विकास) देहरा	01970	233687
14.	सह प्रबन्धक (विकास) जुब्बल	01781	252558
15.	सह प्रबन्धक (विकास) सरकाघाट	01905	231068
16.	सह प्रबन्धक (विकास) काजा	01906	222620
17.	सह प्रबन्धक (विकास) भरमौर	01895	225378

निवेदकः प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कल्याण भवन सोलन–173212

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177–2805015, 94180–15015 फैक्सः 2805015

हर वर्ग सरकार से नाराज फिर भी सता में वापसी करने का दावा

- पैन्शनर को चार साल में कुछ नहीं मिला
- युवा बेरोजगार यात्रा निकालने को हुये मजबूर
- किसानों बागवानों को निकालनी पड़ी आक्रोश रैली
- लोकसेवा आयोग में रह गया एक ही सदस्य
- अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को उच्च न्यायालय ने लगाया दस लाख का जुर्माना

शिमला/शैल। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उसी अनुपात में राजनीतिक गतिविधियां भी तेजी पकड़ती जा रही हो मुख्यमंत्री हर चुनाव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हर जगह करोड़ों की घोषणा हो रही हैं। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये अभी सरकार को पन्द्रह सौ करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने इस पर सवाल उठाते हुये आरोप लगाया है कि सरकारी खर्च पर पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रामलाल के सवाल का जवाब भी उन्हीं के प्रतिबंधी रणधीर शर्मा ने दिया है। रणधीर शर्मा ने रामलाल द्वारा दिये गये कर्ज के आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बताया है। दोनों नेताओं में हुये इस वाकयुद्ध से यह प्रमाणित हो जाता है कि एक भी नेता को सही स्थिति का ज्ञान नहीं है। किसी ने भी 31 मार्च 2020 तक की आयी कैग रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि शायद किसी भी राजनेता ने इस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि इस रिपोर्ट में दर्ज तथ्य किसी के भी होश उड़ा देंगे। मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन के पास इन तथ्यों का कोई जवाब नहीं है। शैल अगले अंक में यह खुलासा अपने पाठकों के सामने रखेगा।

लेकिन अभी जो रिपोर्ट फील्ड से आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणाओं का एक चौथाई भी व्यवहारिक शक्ल नहीं ले पाया है। पांवटा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा घोषित शैक्षणिक संस्थानों में से आधे से ज्यादा फंक्शनल नहीं हो पाये हैं और यही स्थिति अन्य जगह भी है। अभी पैन्शनर्ज संघों ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता करके आरोप लगाया है कि जयराम सरकार अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में उनकी एक भी मांग पूरी नहीं कर पायी है। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले 5,10 व 15 प्रतिशत पैन्शन भत्ता की अदायगी संशोधित पैन्शन पर नहीं कर पायी है। वृद्ध पैन्शनरों को जो 1500 रूपये बढ़ा हुआ चिकित्सा भत्ता नहीं मिल पाया है। पैन्शनर्ज सरकार से बुरी तरह खफा हैं यह स्पष्ट हो चुका है। बेरोजगार युवा रोजगार के लिये कांग्रेस के बैनर तले बेरोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। अभी प्रदेश के किसान और बागवान हजारों की संख्या में आक्रोश रैली निकालकर सचिवालय का घेराव कर चुके हैं। क्योंकि 28 जुलाई को मुख्यमंत्री ने इनके 20 सूत्रीय मांग पत्र को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस पर व्यवहारिक रूप से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और शायद इसीलिये आक्रोश रैली से निपटने के लिये मुख्य सचिव को आगे कर दिया। अब सरकार ने इनसे दस दिन का समय मांगा है। क्या 10 दिन में इनकी मांगों को सरकार स्वीकार कर पायेगी? प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी रखने वालों के अनुसार सरकार किसी भी वर्ग की कोई भी मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं है। सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली कैसे चल रही है इसका खुलासा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये दस लाख के जुर्माने से सामने आ गया है। क्या इस जुर्माने के लिये बोर्ड प्रशासन के खिलाफ कारवाई की जायेगी? यही नहीं आज प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी यह स्थिति आ गयी है कि वहां पर अध्यक्ष समेत छः पद सृजित होने के बावजूद केवल एक ही सदस्य रह गया है। इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता है। ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि इस तरह की कार्यप्रणाली के साथ सरकार की सत्ता में वापसी के दावे कितने विश्वसनीय हो सकते हैं।

क्यों नहीं हो पा रही है दवा नियंत्रक मरवाह के खिलाफ जांच

प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आने के बाद भी कारवाई न होने का अर्थ क्या है

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के दवा नियन्त्रक नवनीत मरवाह के खिलाफ बद्दी के एक सामाजिक कार्यकर्ता एम.सी.जैन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुये एक शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 29-4-2022 को भेजी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जैन के नाम आये पत्र के मुताबिक यह शिकायत 14-5-2022 को मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को कारवाई के लिए भेज दी गई थी लेकिन इस पर एक माह तक कोई कारवाई न होने पर जैन ने 4-6-2022 को फिर प्रधानमंत्री को एक पांच पन्नों का शिकायत पत्र भेजा है। जैन ने इसके हर पन्ने पर हस्ताक्षर किये हुये हैं। जैन ने इस पत्र में कुछ और जानकारियां प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी हैं। जिस तरह से जैन पुनः इस शिकायत को भेज रहा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आरोपों के प्रति पूरी तरह आश्वसत है। जैन की यह शिकायत 30-7-2022 को मुख्य सचिव से प्रधान सचिव स्वास्थ्य को भी जा चुकी है। परंतु अभी तक शायद यह शिकायत विजिलैन्स तक नहीं पहुंच पायी है और न ही इस संद्धर्भ में कोई मामला दर्ज हो पाया है। जयराम सरकार में स्वास्थ्य विभाग सबसे अधिक चर्चा में रहा है। पत्र बम्बों का शिकार भी यह विभाग सबसे अधिक रहा है। इन्हीं विवादों के चलते स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया। विभाग के निदेशक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तारी तक हुई। प्रदेश में बन रही दवाइयों के दर्जनों सैंपल फेल हो चुके हैं। लेकिन किसी भी मामले में किसी भी निर्माता का लाइसेंस तक रद्द नहीं हुआ है। सरकार सो कॉज़ नोटिस से अधिक कारवाई नहीं कर पायी है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेने के प्रति गंभीर नहीं है। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय से आयी शिकायत पर भी चार माह में मामला दर्ज न हो पाये तो इसे कोई भी क्या मानेगा। जबकि चुनाव के वक्त में तो सरकारें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स दिखाने के लिये ऐसे मामलों में तुरन्त कारवाई करती है। जैन द्वारा की गई शिकायत कितनी गंभीर है इसका आकलन पाठक शिकायत पढ़कर स्वयं कर सकते हैं।

पत्र क्रमांकः AMB/2022/461/Complaint

दिनांकः 04.06.2022

सेवा में

प्रधानमन्त्री,
आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः दवा नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश श्री नवनीत मरवाहा के विषय में शिकायत पत्र।

सन्दर्भ मेंः पत्र दिनांक 29.04.2022 के विषय के सम्बन्ध में पूर्व में जांच/ कार्यवाही न होने के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए श्री नवनीत मरवाहा दवा नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध शिकायत पत्र।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दवा नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश श्री नवनीत मरवाहा के विरूद्ध 500 करोड़ रूपये से ऊपर के घोटालों/ भ्रष्ट तरीके से अर्जित धन राशि के विषय में मैने आपको जानकारी दी थी जो कि पत्र दिनांक 14.05.2022 को आपके कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को मार्क करके कार्यवाही हेतु भेजा गया था, परन्तु करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई भी जांच/कार्यवाही भ्रष्टाचारी अधिकारी श्री नवनीत मरवाहा के विरूद्ध नहीं हुई है क्योंकि उक्त भ्रष्टाचारी के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं जोकि मेरे द्वारा शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में मुझे ही धमकाया जा रहा है एवं साक्ष्यों को भी मिटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी मैं आपके समग्र भेज रहा हूँ जो कि निम्न प्रकार से है:-

1. <u>प्रॉडक्ट परमिशनः</u>

नवनीत मरवाहा दवा नियन्त्रक बद्दी हिमाचल प्रदेश द्वारा कुछ दवा कम्पनियों को दवा बनाने के प्रोडक्ट परमिशन जो कि दवा नियन्त्रक भारत सरकार दिल्ली (DCGI) द्वारा New Drug के निर्माण के लिए दी जाती है परन्तु नवनीत मरवाहा द्वारा कुछ कम्पनियों से मोटी रकम (करोड़ों रूपया) लेकर M/s Scot Edil Pharmacia, Life Vision एंव Zeiss Pharma Pvt. Ltd. Baddi एवं अन्य कई कम्पनियों को Approval दे दी गई है। जिससे उक्त कम्पनियों ने करोड़ों रूपया Product monopoly की वजह से कमाया और उक्त कम्पनियों में पैसा भी नवनीत मरवाहा का लगा हुआ है। जिसकी जांच के बाद सब साफ हो जाएगा कि जो Product

9. <u>नवनीत मरवाहा को धर्मशाला में स्थित एक आश्रम में भी हिकाना हैः-</u>

नवनीत मरवाहा के धर्मशाला में स्थित एक आलीशन बंगले के अतिरिक्त एक आश्रम में भी करोड़ों रूपये का लेन-देन होता है जिसमें कुछ संक्षिप्त दस्तावेज भी उपलब्ध है। उक्त आश्रम का संचालन एक मीडिया कर्मी द्वारा किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नवनीत मरवाहा के पैसे का हिसाब किताब रखता है। आश्रम की आड़ में करोड़ों रूपयों का हवाला हो रहा है। यह मीडिया कर्मी स्वयं को किसी मिडिया घराने का Editor कहलाता है एवं मीडिया घराने का गलत इस्तेमाल कर रहा है।

10. <u>नवनीत मरवाह के कुछ दलालों से रोजाना फोन पर सम्पर्कः-</u>

नवनीत मरवाहा के कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों से लेन-देन हैं जोकि देश की सुरक्षा में कुछ अड़चन हो सकती है। उक्त व्यक्तियों में एक व्यक्ति पंकज कपूर है जो कि पंचकुला में रहता है एवं नवनीत मरवाहा के लिए दलाली करता है। प्रतिदिन 25 से 30 बार फोन पर ऐसी क्या बात होती है। इसकी भी जांच से खुलासा हो जाएगा।

कृपया करके उक्त अधिकारी की जांच किसी भी केन्द्रीय ऐजेन्सी के उच्च अधिकारियों से करवायी जाऐ ताकि करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया हुआ पैसा राष्ट्र के काम आ सके। यह पैसा हवाला के जरिये विदेशों में जाने से बचाया जा सकता है।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

M.C. Jain (Socialist)
393, Sector-8,
HUDA, Ambala City
(M) 9416032020

संलग्नः 1. प्रांजल मरवाहा के विदेश भ्रमण की फोटो
2. प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा पूर्व में शिकायत मार्क की प्रति।

To

Shri Narender Modi Ji
Hon'ble Prime Minister
Govt. of India
7, Lok Kalyan Marg,
New Delhi-110001.

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
05 MAY 2022
डाक अनुभाग / DAK SECTION

Dated:28-04-2022

विषयः नवनीत मरवाहा ड्रग कन्ट्रोलर बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के पद पर आसीन होते हुए भ्रष्टाचार के चलते 500 करोड़ का मालिक बन गया।

माननीय महोदय,

1. हिमाचल प्रदेश के दवा निर्माता उद्योगपति पलायर करने पर मजबूर। प्रार्थना यह है कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिला सोलन में नवनीत मरवाहा नाम का अधिकारी राज्य दवा नियंत्रक पिछले कई सालों से इस पद पर आसीन है। यह व्यक्ति भ्रष्टाचार की सीमाओं को लाँघ रहा है और हम उद्योगपतियों का जीना हराम कर